TITLE CODE:- UPHIN51504
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 237
दि. 28.12.2025, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.
Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

अरावली मामले पर सीजेआई का स्वत: संज्ञान, 29 दिसंबर को एससी की तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई

(जीएनएस)।

देश भर में चल रहे 'अरावली बचाओ आंदोलन' और #Save Aravalli की गुंज अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े अहम मुद्दे पर 27 दिसंबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का फैसला किया है।'इस मामले की सुनवाई 29 दिसंबर को तीन जजों की बेंच करेगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मसीह शामिल होंगे। अदालत में इस मामले को "अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा और संबंधित मुद्दे" शीर्षक के तहत संज्ञान में लिया है।

CJI की दखल से बढ़ी अहमियत'अरावली पर्वतमाला को देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है और यह उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन, भूजल स्तर और जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीते कुछ वर्षों में अवैध खनन और अंधाधुंध विकास गतिविधियों के कारण अरावली को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना इस मुद्दे की गंभीरता को दशार्ता है।

केंद्र सरकार पहले ही लगा चुकी है सख्त रोक'सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही केंद्र सरकार ने अरावली पर अपने फैसले को लेकर कदम उठाया था जिसे पर्यावरण विशेषज्ञों ने सरकार का डैमेज कंट्रोल कहा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश जारी करते हुए अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को कहा है। इसका उद्देश्य अरावली के प्राकृतिक स्वरूप को बचाना और पर्यावरणीय क्षति को रोकना है।

केंद्र सरकार का क्या है तर्क?'इतना ही नहीं, MoEF&CC ने

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को पूरे अरावली क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश दिया है।

इसके तहत ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों और जोनों की पहचान की जाएगी, जहां पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और भूदृश्य स्तर पर खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यह प्रतिबंध पहले से चिन्हित क्षेत्रों के अलावा होगा, ताकि अरावली को व्यापक स्तर पर सुरक्षा मिल सके। 'कुछ दिन पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह भी स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन को लेकर कोई छूट नहीं दी है। अदालत ने दो अहम बातें कही हैं- पहली, सरकार के 'ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट' को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दूसरी, कउत्रक्षर को अरावली का विस्तृत नक्शा और सुरक्षा योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब तक यह वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खुदाई या खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?'पर्यावरण और भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अरावली पहाड़ियों को लेकर नई परिभाषा और नियमों को उसी तरह लागू किया गया, तो इसका सीधा असर इस प्राचीन पर्वतमाला के अस्तित्व पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि मौजूदा नियमों के तहत अरावली का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा "पहाड़ी" की श्रेणी से बाहर हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा।'हालांकि केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ खनन पर रोक पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक, अरावली न सिर्फ खनिज संसाधनों से जुड़ी है, बल्कि यह जल स्रोतों के संरक्षण, वायु प्रदूषण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है।

29 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें'अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की सोमवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि अदालत इस मामले में पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन को लेकर दिशा-निर्देश तय कर सकती है। अरावली का भविष्य न सिर्फ कानूनी बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह पर्वतमाला उत्तर भारत की जीवनरेखा कही जाती है।'विशेषज्ञों का मानना है कि सोमवार को होने वाली सुनवाई अरावली के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इस सुनवाई से यह तय होगा कि अरावली को कानूनी और पर्यावरणीय संरक्षण किस स्तर तक मिलेगा और आने वाले सालों में इसकी रक्षा के लिए कौन-सी दिशा अपनाई जाएगी।

यूपीः सीएम योगी बोले पुलिस की इमेज में हुआ है बड़ा बदलाव, अपराधियों के मन में बैठा भय; आम लोगों को मिली राहत

लखनऊ, (जीएनएस)। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय और आम नागरिकों के लिए विश्वास व सम्मान का भाव स्थापित कर रही है। उन्होंने 2017 से पहले प्रदेश की कानून-व्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी। आठ साल के भीतर यूपी पुलिस ने कानून-व्यवस्था में सुधार ने पुलिसिंग की छवि बदली है। यूपी का ह्यरूल ऑफ लॉह्व का मजबूत उदाहरण बन चुका है। इससे अपराधियों में भय के साथ ही जनता में विश्वास बढ़ा है। सीएम ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि यूपी पुलिस के कार्यों की सराहना न सिर्फ देश में हो रही है बल्कि विदेशों में भी हो रही है, लेकिन सराहना के साथ काम का असर धरातल पर दिखे तभी इसे अपनी उपलब्धि समझना चाहिए।

पुलिस मुख्यालय में शनिवार को आयोजित दो दिवसीय ह्यपुलिस मंथनह्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन-2025 में अध्यक्षता कर रहे सीएम ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब लोगों के मन में असुरक्षा का भाव था। वह अपराधियों के दहशत में रहते थे। पुलिस प्रशिक्षण भी कमजोर था लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कानून-व्यवस्था का राज स्थापित हुआ। पुलिसिंग व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। साढ़े आठ साल में 2.19 लाख भर्तियां की गईं। वर्तमान में 60,244 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग चल रही है। सीएम ने बीट पुलिसिंग पर जोर दिया। इस मौके पर सीएम ने ह्यएक्षह्व ऐप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्णा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम ने कहा कि कानून-व्यवस्था बेहतर करने के लिए प्रदेश के सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया गया। वहीं जहां प्रदेश में पहले सिर्फ दो साइबर थाने हुआ करते थे आज प्रत्येक जिले में साइबर थाना है।

हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। अगर फोरेंसिक लैब की बात करें तो वर्तमान में 12 अत्याधुनिक लैब तैयार हो चुकी हैं। छह नई लैब का काम जारी है। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ने अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पहचान बनाई है।

यूपी-112 का रेस्पांस टाइम अब 6-7 मिनट

सीएम ने कहा कि प्रदेश में एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ जैसी स्पेशल यूनिट गठित की गईं जो बेहद प्रभावी साबित हो रही हैं। पुलिस बैरकों को भी हाईटेक बनाया जा रहा है और उनको हर एक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यूपी-112 के बारे में सीएम ने कहा कि एक वक्त 60-65 मिनट रेस्पांस टाइम होता था आज हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद छह से सात मिनट में पीआरवी मौके पर पहुंच रही है।

1- ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से जोड़ा जाए। इससे गांवों की सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। अपराध नियंत्रण पाने में आसानी होगी।

2- बीट पुलिस के सिपाही व दरोगा गांव स्तर पर लगातार जनसंपर्क करें और लोगों से संवाद करते रहें। जमीन स्तर की जानकारी मिलेगी जो कानून-व्यवस्था सुधारे में मदद करेगी।

3- मिशन शक्ति केवल पुलिस प्रयास तक ही सीमित नहीं है। ये सभी विभागों के समन्वय से संभव है। महिला सुरक्षा प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागों को योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा।

4- महिलाओं की सुरक्षा दो स्तरों पर सुनिश्चित करना जरूरी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। परिवार और समाज में ऐसा वातावरण बने, जहां महिलाएं बिना भय के अपनी पीड़ा साझा करें। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर एंटी रोमियो स्क्वॉड व महिला बीट सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मनरेगा : मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान, 5 जनवरी से सड़क पर उतरेगी कांग्रेस

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की अहम बैठक में शनिवार को कई बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से नौ राज्यों और

तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), संसद के शीतकालीन सत्र में पारित G RAM G Bill (जिसने मनरेगा की जगह ली है), और बांग्लादेश में जारी अशांति जैसे विषय प्रमुख रहे।'बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और मनरेगा को खत्म किए जाने के फैसले के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। उहउ बैठक में शीर्ष नेताओं की मौजूदगी'कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था उहउ की इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर समेत अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों के साथ-साथ मौजूदा राजनीतिक हालात और सरकार की नीतियों पर गहन मंथन किया गया।

मनरेगा हटाने पर जनता में गुस्साः खड़गे'बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि मनरेगा को समाप्त कर उसकी जगह 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' कानून लाना जनता के साथ धोखा है।

नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

गांधीनगर, 27 दिसंबर : भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा ने शनिवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

डॉ. शर्मा नेपाल के टूरिज्म प्रवोशन के लिए गुजरात की यात्रा पर आए हैं। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री से यह शिष्टाचार भेंट-बैठक आयोजित की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में गुजरात द्वारा टूरिज्म सेक्टर में जो विश्व आकर्षण स्थापित किए हैं, उसकी डॉ. शर्मा ने प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से टूरिज्म, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाइड्रो एनर्जी एवं मैन्युफैक्चरिंग तथा एजुकेशन सेक्टर में सहभागिता पर मुख्यमंत्री के साथ परामर्श किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग हब बने होने तथा सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में भी अग्रणी बनने को सज्ज हुए होने का विवरण दिया।

इसके अलावा; मुख्यमंत्री ने नेपाल के राजदूत के समक्ष भूमिका दी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिट, सफेद रण जैसे पर्यटन स्थलों और सोमनाथ, द्वारका तथा अंबाजी जैसे आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के साथ गुजरात विश्वभर के पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना है।

नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के बीच इस शिष्टाचार भेंट-बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप तथा नेपाली प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी सहभागी हुए।

चौमूं : पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, इंटरनेट सेवाएं ठप,

जयपुर के चौमूं कस्बे में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने की वजह से विवाद शुरू हो गया था। शुक्रवार तड़के यह विवाद हिंसा में बदल गया। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें आधा दर्जन पुलिसवाले घायल हो गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।'फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतजाम जारी हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 75 आरोपी पत्थरबाजों को अरेस्ट किया है।

ग्रामीण कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योग के लिए हैंडीक्राफ्ट ब्रांड्स को सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, मृगनयनी से प्राकृत तक हर जिले में शॉप

(जीएनएस)।

'मध्य प्रदेश के ग्रामीण कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योग के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। राज्य के प्रमुख हैंडीक्राफ्ट ब्रांड्स - मृगनयनी, विंध्या वैली, कबीरा और प्राकृत - के विक्रय केंद्रों का विस्तार अब जिला स्तर तक किया जाएगा।'यह फैसला प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय कारीगरों को बाजार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विस्तार से न केवल 50 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे, बल्कि टढ की हस्तकला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और कारीगरों की आय में कमी की शिकायतें बढ़ रही हैं।

'मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में एक कार्यक्रम में यह घोषणा की, जहां उन्होंने कहा, "हमारे ब्रांड्स मृगनयनी, विंध्या वैली, कबीरा और प्राकृत प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। इनके विक्रय केंद्रों को जिला स्तर तक विस्तारित कर हम ग्रामीण कारीगरों को सीधा बाजार देंगे। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।" यह योजना 2026 से लागू होगी और पहले चरण में सभी 52 जिलों में कम से कम एक-एक विक्रय केंद्र खोला जाएगा।'ब्रांड्स का महत्वः MP की हस्तकला की पहचान'मध्य प्रदेश सरकार के हैंडीक्राफ्ट ब्रांड्स ग्रामीण कारीगरों की मेहनत का नतीजा हैं। इनका विस्तार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगाः'

मृगनयनीः हैंडलूम और टेक्सटाइल ब्रांड। चंदेरी, महेश्वरी साड़ियां, बैग आदि। कारीगरः 10 हजार+।

विंध्या वैलीः विंध्य क्षेत्र की हस्तकला। लकड़ी के शिल्प, टेराकोटा, बांस उत्पाद।

कबीराः आदिवासी कला पर आधारित। गोंड पेंटिंग, बैल मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल ज्वेलरी।

प्राकृतः प्राकृतिक उत्पाद। हर्बल कॉस्मेटिक्स, ऑर्गेनिक फूड, आयुर्वेदिक सामग्री।'इन ब्रांड्स से 2 लाख+ कारीगर जुड़े हैं। विस्तार से जिला स्तर पर शॉप खुलने से स्थानीय बाजार मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होगी।'योजना की डिटेलः 52 जिलों में विक्रय केंद्र, 50 हजार रोजगार' विस्तार प्लानः हर जिले में कम से कम एक केंद्र। बड़े जिलों में 2-3।

लागतः 500 करोड़ का अनुमानित बजट (2026-2028)।

रोजगारः 50 हजार+ (कारीगर, सेल्स, लॉजिस्टिक्स)।

पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेतहरीश रावत का पाकिस्तानी जासूस वाला एआई वीडियो हटाया, फिर भी जारी है घमासान

(जीएनएस)।

पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के पाकिस्तानी जासूस वाले एआई वीडियो को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से अक वीडियो को हटा दिया है। हालांकि कांग्रेस अब भी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है।'हरीश रावत अब इस मामले में दिल्ली में भी विरोध दर्ज करने जा रहे हैं। इससे पहले हरीश रावत देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय तक पैदल मार्च भी कर सांकेतिक विरोध जता चुके हैं। हरीश रावत ने इस पूरे मामले में देहरादून नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।

बता दें कि उत्तराखंड भाजपा के ऑफिशल फेसबुक इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर हरीश रावत को मुस्लिम टोपी के साथ मुसलमानों का हितेषी दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट की गई थी। इसके अलावा एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर कई अलाग-अलाग अकाउंट से वायरल किया गया, जिसमें हरीश रावत को पाकिस्तान जासूस बताया जा रहा था। इस वीडियो पर भी हरीश रावत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। 'हरदा का आरोप था कि उनकी छवि धूमिल करने के साथ ही उनकी जान को भी खतरा है। हरीश रावत ने इस पूरे मामले में देहरादून नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद हरीश रावत ने एसएसपी देहरादून से भी शिकायत दर्ज कराई। बाद में हरीश रावत ने

बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। जब हरदा को रास्ते में रोका गया तो हरदा ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया।'इन सब प्रकरण के बाद भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो हटा दिया गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर हरीश रावत का कहना है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे दिल्ली में भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे पाकिस्तानी जासूस और पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुये दिखाए जाने पर चिंता प्रकट की। लोगों ने कहा कि इस तरीके अक का दुरुपयोग कर इस तरीके से मुझे चित्रित किया जाना, यह निंदनीय है, बहुत लज्जाजनक है।'कुछ लोगों ने मुझे आग्रह किया कि मैं दिल्ली में भी आऊं और इस विषय में पूरी स्थिति अपने मित्रों और दिल्ली के प्रबुद्ध लोगों के सामने रखूं। हरदा ने कहा कि वह 20 जनवरी, 2026 के बाद दिल्ली में भी गढ़वाल भवन में इस संबंध में अपने मित्रों और सहयोगियों की एक बैठक कर उन सब लोगों के सामने भाजपा के कुत्सित इरादों की पोल खोलेंगे।

सम्पादकीय

आने वाले दिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ही बहुत भारी!

अमेरिका के एक सनकी पत्रकार ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारतीय लोगों, उनके घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं मंदिरों पर हमले होंगे, इसलिए सभी भारतीयों को देश से बाहर निकालना ही इस संकट का एकमात्र हल है। यह कोई साधारण पत्रकार नहीं है। इसका नाम है मैट फाना जो अमेरिका में दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट भी है। उसने अपने देश के प्रशासन को आगाह किया है कि भारतीयों के खिलाफ हिसा करने वाले पाकिस्तान मूल, हिस्पैनिक अमेरिकी और अप्रीकी अमेरिकी होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी अपने मस्तिष्क में यह बात बैठा चुके हैं कि अमेरिका ब्र१ाण्ड का ऐसा देश है जहां रहने के लिए दुनिया के हर देश के लोग लालायित रहते हैं। पत्रकार ने यदि 2026 में भारतीयों पर हमले की बात कही है तो इसे गंभीरता से लेना ही चाहिए। लेकिन इस पत्रकार को 2026 की एक बात को और भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि 1 जनवरी यानि एक सप्ताह भारत ब्रिक्स (ब्राजील, इंडिया, रूस, चीन और साउथ अप्रीका) का अध्यक्ष बन जाएगा। मतलब यह कि अब अमेरिका का वर्चस्व खत्म होने वाला है। इस पत्रकार की तरह ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत रूस और चीन को एक साथ ला दिया है। इसलिए तीनों सरकारों के बीच अमेरिका के खिलाफ इतनी जबरदस्त सहयोगत्मक भावना पैदा हो गई है कि आने वाला दिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ही बहुत भारी पड़ने वाली है। ट्रंप की धमकी का परिणाम यह हुआ कि ब्रिक्स देशों के बीच वृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना शुरू कर ही दिया है साथ ही ये देश ग्लोबल साउथ के लिए खाद्या सुरक्षा को रणनीतिक मान्यता देने की तैयारी में हैं। यदि वृषि व्यापार प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, जलवायु अनुवूल-खेती और मूल्य श्रृंखला विकास में साझेदारी का विकास कर लें तो क्या दबंगई रह जाएगी अमेरिका की। आज अमेरिका इस मुगालते में है कि दुनिया का कोई भी देश उसके समान समृद्ध नहीं है किन्तु सच तो यह है कि कच्चे तेल का उत्पादन, सोने के भंडार, आर्थिक आकार और खाद्या आत्मनिर्भरता भूराजनीति में सौदेबाजी की ताकत का निर्धारण करते हैं। ग्यारह ब्रिक्स देशों का इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका के लिए ब्रिक्स बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है क्योंकि विश्व ऊर्जा सांख्यिकी की समीक्षा 2025 के मुताबिक 2024 में ब्रिक्स देशों ने दुनिया के लगभग 42 प्रतिशत तेलों का उत्पादन किया। यही नहीं विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का 20 प्रतिशत स्वर्ण भंडार है। यही नहीं ब्रिक्स देश विश्व अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तो 2024 में वैश्विक घरेलू उत्पाद ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी में 29 प्रतिशत का योगदान रहा है। असल में अमेरिका की सबसे बड़ी नाराजगी भारत से यह है कि 2025 के अगस्त में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने में व्यस्त थे उसी वक्त भारत ने अमेरिकी डालर के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए एक परिपत्र जारी किया जिसके तहत ब्रिक्स देशों को अपना 100 प्रतिशत व्यापार भारतीय रूपए में करने की अनुमति मिल गई है। वैसे तो अमेरिकी डालर का वर्चस्व पहले से ही कम होना शुरू हो गया था किन्तु अब यदि ब्रिक्स देश रुपए में व्यापार शुरू कर देंगे तो डालर का क्या होगा! भारत को इस वास्तविकता का पहले से ही एहसास था कि अपने डालर पर इतरा रहे अमेरिका को जब भी उसके डालर के फजीहत की जानकारी होगी तो उसका तिलमिलाना स्वाभाविक होगा। अमेरिका का पूरा इकोसिस्टम जो भारत को यह धमकियां देता रहता था। उसके उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे, उसकी यह जानने के बाद अब सिट्टी-पिट्टी गुम होती दिख रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बैंकों को बिना पूर्ण अनुमति के अधिक वोस्नें खाते खोलने का निर्देश दे दिया है। इस नीति के तहत अन्य देशों के निर्यातक और आयातक अब समर्पित वोस्त्रों खातों के माध्यम से रूपए में अपना व्यापार कर सकते हैं। फिर तो वैश्विक बाजार में डालर के वर्चस्व में और भी गिरावट आना तय है। बहरहाल यदि अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ हमले होते हैं, तो यह अमेरिकी स्टेट अथारिटी की जिम्मेदारी होगी कि वह उनकी रक्षा करे।

उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 8 महीनों में 31 क्षेत्रों में 45 करोड़ रुपये की राशि वापस दिलवाई'

ई-कॉमर्स क्षेत्र में 32 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई; यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 3.5 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई'

(जीएनएस)।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख पहल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी से पहले निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।'25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 तक आठ महीने की अवधि के दौरान, हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में राशि वापिस दिलवाने के दावों से संबंधित 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए 45 करोड़ रुपये की राशि के वापिस दिलवाई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमेबाजी से पहले, एनसीएच विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाती है जिससे उपभोक्ता आयोगों पर बोझ कम होता है।'क्षेत्रवार निष्पादन'ई-कॉमर्स क्षेत्र में शिकायतों और वापिस दिलवाई गई राशि की मात्रा और संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई जिसमें 39,965 शिकायतों के परिणामस्वरूप 32 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा जिसमें 4,050 शिकायतें दर्ज की गई और 3.5 करोड़ रुपये की राशि वापिस दिलवाई गई।'ई-कॉमर्स क्षेत्र से राशि वापिस दिलवाने से संबंधित शिकायतें देश के सभी हिस्सों से प्राप्त हुई जिनमें प्रमुख महानगरों से लेकर दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की राष्ट्रव्यापी पहुंच, सुगमता और प्रभावशीलता को दशार्ता है।'कुल वापिस दिलवाई गई राशि में 85 प्रतिशत से अधिक का योगदान देने वाले शीर्ष पांच क्षेत्रों, प्राप्त शिकायतों की संख्या और संबंधित वापिस दिलवाई गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:'क्रम संख्या'क्षेत्र'कुल शिकायतें'कुल वापसी राशि (रुपये में)'1'ई-कॉमर्स'39, 965'320, 680, 198'2'यात्रा पर्यटन'4, 050'35, 222, 102'3'एजेंसी सेवाएं'957'13, 497, 714'4'इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद'635'11, 725, 231'5'एयरलाइंस'668'9, 556, 843' 'कुल'46, 275'39, 06, 82, 088' 'इस उपलब्धि के पीछे का एक प्रमुख कारण साझेदारों की संख्या में विस्तार है जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की सामूहिक क्षमता में वृद्धि हुई है। यह

संबंधित हितधारकों की सशक्त भागीदारी को दशार्ता है जो उपभोक्ता कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए उनकी जवाबदेही की पुष्टि करता है।'25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 की अवधि में 45 करोड़ रुपये की राशि की त्वरित वापसी न केवल हेल्पलाइन की प्रभावशीलता और तत्परता दशार्ती है बल्कि समयबद्ध और परेशानी मुक्त शिकायत निवारण सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी दशार्ती है। यह मुकदमेबाजी से पहले के चरण में एक आवश्यक माध्यम के रूप में एनसीएच के महत्व को और मजबूत करता है जो बाजार में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।'उपभोक्ता पर प्रभाव - उदाहरण:'राजस्थान के जोधपुर के एक उपभोक्ता ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खराब कुर्सियाँ प्राप्त करने के बाद शिकायत दर्ज कराई। समाधान चाहा, उपभोक्ता ने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन लगातार पाँच बार समान वापिस लेना रद्द कर दिया गया जिससे मामला अनसुलझा रह गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के हस्तक्षेप से मामले का तुरंत समाधान हुआ और उपभोक्ता को पूरी राशि वापस कर दी गई। उपभोक्ता ने हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'मेरे जैसे ठगे गए उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन का बहुत-बहुत धन्यवादङ्ग आपका बहुत-बहुत आभार ह्व'कर्नाटक के बेंगलुरु निवासी एक उपभोक्ता ने वार्षिक इंटरनेट प्लान खरीदा था और उसके खाते से राशि काट ली गई थी। हालांकि, कनेक्शन कभी लगाया ही नहीं गया। जब उसने ग्राहक सेवा से संपर्क किया तो उसे आश्वासन दिया गया कि 10 कार्य दिवसों के भीतर राशि लौटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। कई बार कॉल करने और शिकायत करने के बावजूद, उपभोक्ता को चार महीने बाद भी राशि वापिस नहीं मिली। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के प्रभावी हस्तक्षेप से कंपनी ने तुरंत राशि लौटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी। समाधान पर संतोष व्यक्त करते हुए उपभोक्ता ने कहा, "यह एक अच्छा अनुभव रहा। अन्यथा, राशि वापिस पाना मुश्किल था।"'तमिलनाडु के चेन्नई के एक उपभोक्ता ने उड़ान से 96 घंटे से अधिक पहले अपना टिकट रद्द कर दिया था। इसके बावजूद, उपभोक्ता के बार-बार अनुरोध करने पर भी कंपनी ने राशि वापिस नहीं लौटाई। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के त्वरित हस्तक्षेप से राशि वापिस लौटा दी गई। एनसीएच के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उपभोक्ता ने कहा, "एनसीएच को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रयासों से बहुत प्रसन्न हूं।"'ये मामले मुकदमेबाजी से पहले की प्रभावी व्यवस्था के रूप में एनसीएच की भूमिका को दशार्ते हैं जो उपभोक्ताओं को लंबी कानूनी कार्यवाही के बिना सुलभ और समय पर शिकायत निवारण प्रदान करता है।'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन तक पहुंच'यह हेल्पलाइन देशभर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी से पहले ही शिकायतों के निवारण हेतु एक सुलभ केंद्र के रूप में उभरी है । उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

सीएक्यूएम ने 26.12.2025 को गुरुग्राम में एमसीजी के रखरखाव वाले 125 सड़क खंडों का व्यापक निरीक्षण किया' धूल नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में काफी कमियां देखी गईं

सीएक्यूएम ने 26.12.2025 को गुरुग्राम में एमसीजी के रखरखाव वाले 125 सड़क खंडों का व्यापक निरीक्षण किया' धूल नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में काफी कमियां देखी गईं; जमीनी स्तर पर उपायों को मजबूत करने के निर्देश

(जीएनएस)।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गुरुग्राम में 26.12.2025 को सड़क सफाई और झाडू लगाने के कार्यों की समीक्षा करने और गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) के रखरखाव वाले 125 सड़क खंडों की जांच के लिए एक व्यापक अभियान चलाया।'यह निरीक्षण मौजूदा श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के वैधानिक ढांचे के तहत निरंतर निगरानी और प्रवर्तन प्रयासों के हिस्से के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य धूल कम करने के उपायों के साथ जमीनी स्तर पर अनुपालन का मूल्यांकन करना और सड़क की धूल, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू), निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित (सी एंड डी) अपशिष्ट और खुले में जलाने के मामलों जैसे संबंधित मुद्दों की पहचान करना था।'आयोग ने गुरुग्राम में एमसीजी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 125 सड़क खंडों के निरीक्षण के लिए कुल 17 निरीक्षण दल गठित किए, जिनमें हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की 15 टीमें और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की दो टीमें शामिल थीं। निरीक्षण दलों द्वारा भू-टैग और समय-चिह्नित फोटोग्राफिक दस्तावेज एकत्र किए गए और समेकित निरीक्षण रिपोर्ट के भाग के रूप में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये।'निष्कर्षों से पता चला कि निरीक्षण किए गए 125 सड़क खंडों में से 34 खंडों में धूल का स्तर अत्यधिक था, 58 खंडों में मध्यम स्तर की धूल थी, 29 खंडों में धूल की तीव्रता कम थी, जबकि केवल चार खंड पूरी तरह धूल रहित थे। अत्यधिक धूल वाले कई खंडों में ठोस अपशिष्ट और निर्माण एवं तोड़फोड़ अपशिष्ट का भारी संचय पाया गया। इसके साथ ही खुले में जलाने के कई मामले भी सामने आए, जो सड़क रखरखाव, अपशिष्ट प्रबंधन और जमीनी स्तर पर प्रवर्तन में गंभीर कमियों को दशार्ते हैं।'गुरुग्राम के विभिन्न वार्डों और सेक्टरों में कई सड़क खंडों, जिनमें आवासीय कॉलोनियां, आंतरिक सड़कें और मुख्य मार्ग शामिल हैं जिन पर लगातार धूल जमा होने और कचरा फेंके जाने की समस्या पाई गई। कई स्थानों पर खुले में कचरा जलाने और अव्यवस्थित कचरे ने धूल की समस्या को और भी बदतर बना दिया जिससे तत्काल सुधारात्मक उपायों और संबंधित एजेंसी द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता महसूस की गई है।'आयोग ने पाया कि समग्र निरीक्षण परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि एमसीजी की ओर से जमीनी स्तर पर कार्यों को काफी मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें विशेष रूप से नियमित यांत्रिक सफाई, एकत्रित धूल और कचरे को समय पर उठाकर वैज्ञानिक तरीके से निपटाने, सक्रिय जल छिड़काव और धूल-नियंत्रण उपायों के संबंध में, और खुले में आग जलाने पर सख्त रोक लगाने के संबंध में ध्यान दिया गया है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों की स्थिति में स्पष्ट सुधार सुनिश्चित करने और धूल एवं कचरे के पुनः संचय को रोकने के लिए निरंतर और केंद्रित प्रयास आवश्यक हैं।'आयोग ने दोहराया कि धूल नियंत्रण और खुले में आग जलाने की रोकथाम के लिए वैधानिक निदेर्शों और जीआरएपी उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान पूरे एनसीआर में नियमित रूप से जारी रहेंगे। आयोग क्षेत्र में स्वच्छ, हरित और धूल रहित सड़कों को सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है।'

शुभमन गिल से लेकर केएल राहुल ने मचाया गदर, 2025 में सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

(जीएनएस)।

साल 2025 टेस्ट क्रिकेट के लिए बल्लेबाजों का साल साबित हुआ, जहां अलग-अलग टीमों के स्टार खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से रन बरसाकर कई यादगार पारियां खेलीं। लंबे फॉर्मेट में धैर्य, तकनीक और निरंतरता की असली परीक्षा होती है और इस कसौटी पर कुछ बल्लेबाज बाकी सबसे आगे नजर आए।'भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पूरे साल टेस्ट क्रिकेट में दबदबा बनाए रखा। आइए नजर डालते हैं 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों पर, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया।

रँ्रुेल्ल्ॅ'' ल्लि' ' १ँ४"शुभमन गिल (भारत)'साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े रन-स्कोरर शुभमन गिल रहे। उन्होंने 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 983 रन बनाए। 70.21 की शानदार औसत के

साथ गिल ने 269 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और पूरे साल में 5 शतक जमाए। लंबे समय तक क्रीज पर टिककर खेलने की उनकी क्षमता ने भारत की टेस्ट बल्लेबाजी को नई मजबूती दी।'ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)'ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड ने 2025 में 11 टेस्ट मैचों की 21 पारियों में 817 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 170 रन रहा और उन्होंने 2 शतक व 3 अर्धशतक लगाए। आक्रामक अंदाज में रन बनाने वाले हेड ने तेज गति से मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई।'केएल राहुल (भारत)'केएल राहुल ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट में भरोसेमंद प्रदर्शन किया। उन्होंने 10 मैचों की 19 पारियों में 813 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे। 45 से अधिक की औसत के साथ राहुल ने विदेशी परिस्थितियों में भी भारत के लिए अहम योगदान दिया।'जो रूट (इंग्लैंड)'इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने 2025 में एक बार फिर अपनी निरंतरता साबित की। उन्होंने 10 टेस्ट मैचों की 18 पारियों में 805 रन बनाए और 4 शतक जड़े। 50 से ऊपर की औसत के साथ रूट इंग्लैंड की टेस्ट टीम की सबसे मजबूत कड़ी बने रहे।'हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)'युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रभाव छोड़ा। उन्होंने 10 मैचों की 18 पारियों में 771 रन बनाए। 158 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर ब्रूक ने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का ऐलान, स्पीकर से लेकर एंट्री फीस तक हर डिटेल जान लें

(जीएनएस)।

हर साल की तरह इस बार भी देश भर के साहित्य और कला प्रेमी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का इंतजार कर रहे हैं। यह महोत्सव साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति से जुड़े दिग्गजों को एक मंच पर लाने वाला है। आयोजकों के मुताबिक, JLF 2026 का आयोजन 15 जनवरी से 19 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित साहित्यिक महोत्सव का आयोजन जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में होगा।'इस बार जेएलएफ में

लेखक, कवि, विचारक, इतिहासकार और कलाकार हिस्सा लेंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को 'दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक शो' कहा जाता है और हर साल इसमें लाखों साहित्य प्रेमी शामिल होते हैं। इस साल समारोह की एंट्री फी से लेकर स्पीकर्स तक की डिटेल जानें:

JLF 2026 में 500 से अधिक वक्ताओं और 300 से ज्यादा सत्रों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है। फिल्म, कला और साहित्य जगत की हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी।'- इस बार के प्रमुख वक्ताओं में बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई, मशहूर लेखिका बानू मुश्ताक, कवयित्री एलिस ओसवाल्ड, लेखक आनंद नीलकंठन और कला समीक्षक एंड्र्यू ग्राहम-डिक्सन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नाम शामिल हैं।'- साहित्यिक सत्रों में इतिहास, राजनीति, तकनीक, समाज और समकालीन वैश्विक मुद्दों पर गहन चचार्एं होंगी। टिकट और रजिस्ट्रेशन डिटेल'JLF 2026 के लिए अलग-अलग श्रेणियों में टिकट उपलब्ध होंगे। छात्रों के लिए ₹100 में सभी पांच दिनों की एंट्री मिलेगी, जबकि सामान्य दर्शकों के लिए टिकट ₹200 से शुरू होंगे। 'फ्रेंड ऑफ द फेस्टिवल (FOF)' श्रेणी में ₹14,000 से शुरू होने वाले टिकट पर वीआईपी सुविधाएं, डेलिगेट लाउंज और लंच की सुविधा मिलेगी। म्यूजिक स्टेज के लिए टिकट ₹499 से शुरू होंगे।

JLF 2026: साहित्य के साथ कलाओं का भी लें लुत्फ'जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यहां जयपुर बुकमार्क के जरिए प्रकाशकों और लेखकों को बिजनेस नेटवर्किंग का मौका मिलेगा। वहीं जयपुर म्यूजिक स्टेज पर शाम के समय प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा संगीत प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा पुस्तक विमोचन, रचनात्मक कार्यशालाएं और हस्तशिल्प बाजार भी महोत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेंगे।

सानिया किन्नर बनीं पुलिस में होमगार्ड, कभी गांव वालों ने ताना देकर भगाया, खाकी वर्दी देख कर रहे सैल्यूट

(जीएनएस)।

जिस सानिया को कभी गांव में 'नाचने वाली' कहकर ताने मिले, जिनके सपनों को किन्नर कहकर कुचल दिया गया, आज उसी सोनिया किन्नर ने इतिहास रच दिया है। सोनिया बिहार पुलिस में थर्ड जेंडर कैटेगरी में भर्ती होने वाली होमगार्ड हैं। पुलिस में होमगार्ड की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब सोनिया अपने गांव पहुंची तो जिन आंखों में उनके लिए नफरत और उपेक्षा थी, आज उन्हीं आंखों में सम्मान नजर आया, और वही हाथ जो कभी उन्हें भगाने को उठे थे, आज सोनिया को खाकी वर्दी में सैल्यूट कर रहे हैं।'सानिया किन्नर की यह कहानी सिर्फ नौकरी पाने की नहीं, बल्कि पहचान, आत्मसम्मान और समाज की सोच बदल देने वाले साहस की कहानी है। बिहार पुलिस में भर्ती होने के बाद सोनिया के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जिसमें किन्नर समाज की इस बेटी को खूब सम्मान मिल रहा है। इन वीडियोज में कोई सोनिया की आरती उतार रहा है तो कोई इन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहा है।

सोनिया ट्रेनिंग कर पहुंची गांव, हुई भावुक'तमाम सोशल मीडिया प्ॅ लेटफार्म को दिए गए इंटरव्ॅ यू में सोनिया काफी भावुक नजर आईं। जैसे ही थर्ड जेंडर को पुलिस में भर्ती करने का अवसर दिए जाने को ऐलान किया तभी मैंने फॉर्म भरकर दिन-रात मेहनत शुरू कर दी।

ट्रेनिंग पूरी करके अपने किन्नर समाज के साथियों के पास पहुंचने पर जब भव्य स्वागत किया गया तो उनकी आंखें नम हो गईं। सोनिया ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखें, बहुत अपमान सहा, लोग नाचने वाली किन्नर कहकर मुझसे नफरत करते थे।' सोनिया ने बताया कि वो ताउम्र ऐसी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने पढ़ाई की। बिहार सरकार द्वारा

मैथ आनर्स में इरउ कर रही सोनिया बनना चाहती हैं दरोगा'सोनिया ने बताया जब परीक्षा की तैयारी के लिए भागती-दौड़ती थी, तब भी लोग मजाक बनाते थे लेकिन मैं उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ती रही। आज मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी कर होमगार्ड बन चुकी हूं। सोनिया ने बताया वर्तमान समय में वो मैथ ऑनर्स में बीएससी फाइनल इयर की पढ़ाई कर रही हैं।

वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में बने कप्तान, वर्ल्ड कप की टीम में भी किए गए शामिल

(जीएनएस)।

वैभव सूर्यवंशी अब वर्ल्ड कप में अपने बल्ले का जादू चलाते हुए दिखाई देंगे। बीसीसीआई (BCCI) ने टीम की घोषणा करते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए वैभव सूर्यवंशी का चयन भी किया है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के उभरते हुए सितारे आयुष म्हात्रे (Ayush MhÔtre) को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है। वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए कप्तानी मिली है।'आयुष ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल की तैयारियों में अपने प्रदर्शन से चयनकताओं को बेहद प्रभावित किया है। वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से धमाका करते हुए दुनिया को हैरान करने का काम किया है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारत की अंडर 19 टीम खेलेगी, उस टीम में भी वैभव का नाम है।

'मुंबई से ताल्लुक रखने वाले आयुष म्हात्रे को हाल ही में आईपीएल 2025 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की देखरेख में निखर रहे आयुष अब अंडर 19 विश्व कप में देश का नेतृत्व करेंगे। आयुष को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और शांत दिमाग के लिए जाना जाता है, जो उन्हें कप्तानी के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाता है।'इस टीम में सबसे बड़ा नाम बिहार के 14 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी का है। वैभव ने हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़कर इतिहास रचा था। आईपीएल ऑक्शन में भी वे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने जिन्हें पिछले साल राजस्थान रॉयल्स ने करोड़ों की बोली लगाकर खरीदा। उनकी मौजूदगी से भारतीय बल्लेबाजी क्रम और भी मजबूत नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए सूर्यवंशी को कप्तान बनाया गया है, यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है।'

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

टर्मिनेटिंग / ओरिजिनेटिंग ट्रेन की सुविधा के साथ उत्राण स्टेशन का किया जा रहा है विकास

भारतीय रेल की अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों में रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता दोगुनी करने की योजना' 'यात्रा की मांग में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए, भारतीय रेल द्वारा अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करने की योजना है। आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है।

इस दिशा में वर्ष 2025 -26 के दौरान वडोदरा मंडल के प्रतापनगर स्टेशन पर दो नए प्लेटफार्म का निर्माण किया गया। उत्राण स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 3 एवं 4 के विस्तार के साथ अमृत भारत स्टेशन के सभी कार्य पूरे कर लिए गए है। टर्मिनेटिंग / ओरिजिनेटिंग ट्रेन की सुविधा के साथ उत्राण स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिसमे नए हाई लेवल प्लेटफार्म का निर्माण, अप दिशा के प्लेटफार्म के विस्तार और अन्य यात्री सुविधाओं के कार्य शामिल है।' 'वडोदरा मंडल पर शॉर्ट टर्म यानि अगले दो वर्ष के अंतर्गत रानोली स्टेशन पर 2 पिट लाइनों एवं एक स्टेब्लिंग लाइन का निर्माण तथा उत्राण स्टेशन पर 2 नए प्लेटफार्मों का निर्माण किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, लॉन्ग टर्म यानि 3 से 5 वर्ष की योजना के अंदर प्रतापनगर स्टेशन पर 1 पिट लाइन एवं 1 स्टेबलिंग लाइन का निर्माण प्रस्तावित है।' 'इसके अतिरिक्त प्रतापनगर और उत्राण में कोचिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।' 'वर्ष 2030 तक रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा अधोसंरचना विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमेनिम्न कार्य शामिल होंगे:' ⁄. मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना।'शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान और निर्माण करना।'. मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं।'५. विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।' 'केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस सम्बन्ध में कहा, 'हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और अनुभागीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार होगा।

4 बार की टीएमसी सांसद के मां और बेटों को चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस, ये है मामला

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल में रक्क्ष (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद का दौर जारी है। तृणमूल कांग्रेस (ळटउ) ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अनियमितताओं और जल्दबाजी के आरोप लगाए हैं। इस बीच टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के परिवार के सदस्यों को भी सुनवाई के लिए नोटिस भेजे गए हैं। विसंगतियों के आधार पर सांसद की मां और और बेटों समेत चार सदस्यों को नोटिस थमाया है।'बारासात से चार बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार के दोनों बेटों को रक्क्षप्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए बुलाया गया है। यही नहीं, उनकी मां और बहन को भी संबंधित बीडीओ कार्यालय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक, सांसद के परिवार के सदस्य शनिवार (27 दिसंबर) को ही बीडीओ दफ्तर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

टीएमसी की दिग्गज नेता'बारासात से चार बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार को ममता बनर्जी के करीबी लोगों में शुमार किया जाता है। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ उन्होंने संसद में जोरदार आवाज उठाई थी। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के दौरान वह बेहोश भी हो गई थीं। हालांकि, उनके परिवार के सदस्य बीडीओ दफ्तर में जाकर अपना पक्ष रखेंगे।'काकोली ने बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में उनके दोनों बेटों के नाम गायब थे, जबकि वे सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को यह तक नहीं पता कि सुनवाई में उनसे क्या पूछा जा रहा है और उनके नाम जबरन सूची से हटाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

टीएमसी का आरोप है कि रक्क्ष प्रक्रिया बेहद जल्दबाजी में कराई जा रही है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी इस प्रक्रिया के त्रुटिपूर्ण होने का दावा कर चुके हैं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि जो काम आम तौर पर दो साल में पूरा होता है, उसे सिर्फ दो महीनों में क्यों निपटाया जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आने के बाद कई चौंकाने वाली गड़बड़ियां उजागर हुई हैं।

बंगाल एसआईआर में सामने आई हैं कई त्रुटियां'- डानकुनी नगर पालिका के तृणमूल पार्षद सूर्या डे के नाम के आगे 'मृत' दर्ज होना, माकपा राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के बेटे के सरनेम में गलती और मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय के नाम में त्रुटि जैसे मामले सामने आए हैं।'

सीमा शुल्क मंजूरी सुविधा समिति की बैठक ने हितधारकों के विश्वास को मजबूत किया'

इस बैठक में एफएसएसएआई, प्लांट क्वारंटाइन, ड्रग कंट्रोलर सहित सहयोगी सरकारी एजेंसियां; कस्टम्स ब्रोकर, एसोचैम, जीजेईपीसी के अलावा संरक्षक, आयातक, निर्यातक और विभागीय अधिकारियों जैसे हितधारक एक साथ आए।'

(जीएनएस)।

दिल्ली सीमा शुल्क विभाग द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के कल्पना चावला सम्मेलन कक्ष में दिल्ली जोन के मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में सीमा शुल्क मंजूरी सुविधा समिति (सीसीएफसी) की बैठक आयोजित की गई ।''इस बैठक में एफएसएसएआई, प्लांट क्वारंटाइन और ड्रग कंट्रोलर सहित सहयोगी सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ कस्टम्स ब्रोकर, एसोचैम और जीजेईपीसी जैसे व्यापार संघों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीमा शुल्क मंजूरी प्रणाली में शामिल हितधारकों की व्यापक विविधता को दर्शाते हुए, इसमें संरक्षक, आयातक, निर्यातक और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।''विचार-विमर्श के दौरान, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा शुरू की गई हालिया नीति और डिजिटल पहलों का उल्लेख किया गया। जिसमें दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर उनके कार्यान्वयन ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया।

हितधारकों ने प्रमुख परिचालन संबंधी मुद्दे उठाए जिन पर रचनात्मक रूप से चर्चा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यावहारिक परिणाम निकले जो इस सुविधा को मजबूत करेंगे और दक्षता में सुधार करेंगे। बैठक के पारदर्शी और सहयोगात्मक संचालन की व्यापक रूप से सराहना की गई, जिससे सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में विश्वास बढ़ा और निर्यात एवं आयात समुदाय में समन्वय को बढ़ावा मिला।''दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और कानून के दायरे में व्यापार सुविधा को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत पारदर्शिता, सुलभता और दक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये मूल्य न केवल सीमा शुल्क के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विश्वास निर्माण और यह सुनिश्चित करने के लिए भी आधार का काम करते हैं कि हितधारक प्रशासन के साथ खुलकर संवाद करने में सक्षम महसूस करें।'भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार में सुगमता एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए सीमा शुल्क विभाग, सहयोगी एजेंसियों, संरक्षकों और व्यापारिक समुदाय के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक है। निर्णय लेने में पारदर्शिता, प्रक्रियाओं में सुगमता और संवाद एवं समस्या-समाधान के लिए खुली नीति को अपनाकर, दिल्ली सीमा शुल्क विभाग विश्वास, दक्षता और साझा उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है।

कोर्ट ने सजा दी, कोर्ट ने ही जमानत दी, तो हंगामा क्यों?', कुलदीप सेंगर के समर्थन में क्या बोल गए बृजभूषण

(जीएनएस)।

उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित होने के बाद देशभर में उठे विरोध के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सजा देने वाली और सजा निलंबित करने वाली संस्था एक ही है, यानी अदालत, तो फिर इस फैसले पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है।

'सजा भी कोर्ट ने दी, राहत भी कोर्ट ने दी''UP TAK की खास पॉडकास्ट सीरीज 'यूपी की बात' में बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि कुलदीप सेंगर को सजा भी अदालत ने दी और सजा निलंबित करने का फैसला भी अदालत का ही है। उनके मुताबिक, जब ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया था, तब उसी फैसले का खूब स्वागत किया गया। लेकिन अब जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित की है, तो उसी न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अगर अदालत के एक फैसले पर भरोसा किया जाता है, तो दूसरे फैसले पर भी वही भरोसा दिखना चाहिए। वरना इसका मतलब यही निकलेगा कि लोगों को अदालत पर भरोसा नहीं है, बल्कि वे फैसले अपनी सुविधा के हिसाब से स्वीकार

धरना-प्रदर्शन को बताया 'नाटक''बृजभूषण शरण सिंह ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित होने के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों को सीधे तौर पर नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह देश भावनाओं से नहीं, कानून से चलता है। नैतिकता के नाम पर किसी को सजा या फांसी नहीं दी जा सकती। यहां फैसला कानून करता है और कानून का मतलब है अदालत।'उनका कहना था कि अगर किसी को हाई कोर्ट के फैसले से आपत्ति है, तो उसके लिए संवैधानिक रास्ता मौजूद है। लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आगे की अदालतों में अपील कर सकते हैं। लेकिन सड़कों पर उतरकर हंगामा करना और दबाव बनाना न्यायपालिका के सम्मान के खिलाफ है।

'प्रश्न उठाने का मतलब कोर्ट पर भरोसा नहीं''बृजभूषण ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि कुलदीप सेंगर के मामले में हर कदम न्यायपालिका ने उठाया है। सजा भी कोर्ट ने दी, जमानत और सजा निलंबन भी कोर्ट ने ही किया। ऐसे में सवाल उठाने का सीधा मतलब यही है कि लोग अदालत की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि जब अदालत ने सजा सुनाई थी, तब सबको अच्छा लगा।

पेंशन संबंधी 1087 लंबित शिकायतों का निवारण किया गया'

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 24.12.2025 को सुश्री रचना शाह, सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अध्यक्षता में 15वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया'

'जन संवाद' के माध्यम से मिली सफलता की कहानियाँ शिकायतों के त्वरित समाधान और पेंशनभोगियों के लिए गरिमा एवं वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दशार्ती हैं

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डाक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय आदि के अंतर्गत आने वाले 30 विभागों/मंत्रालयों से संबंधित पेंशनभोगियों की 1087 लंबित शिकायतों के निवारण के लिए 24.12.2025 को आयोजित पेंशन अदालत में सुनवाई की गई जिनमें से 815 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया जो पेंशनभोगियों को समय पर न्याय दिलाने में इस पहल की दक्षता को दशार्ता है।'24.12.2025 को आयोजित अदालत से कई हार्दिक सफलता की कहानियां सामने आई। पेंशनभोगियों द्वारा झेली गई कठिनाइयों को समझने और पेंशन अदालत की व्यवस्था के माध्यम से उन्हें उनके लंबे समय से लंबित अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ मामलों के अंश नीचे दिए गए हैं।'श्री सत्यम मिश्रा'प्रयागराज निवासी श्री सत्यम मिश्रा की शिकायत 114 दिनों से अधिक समय से लंबित थी। शिकायत जुलाई 2024 से असाधारण पेंशन के रूप में पेंशन लाभ जारी न होने से संबंधित थी। उन्होंने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की। बीएसएफ के अधिकारियों ने पेंशन अदालत में सूचित किया कि उचित कार्रवाई के बाद मामले का निपटारा कर दिया गया है और अनुग्रह राशि सहित 5,73,728/- रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि उनकी असाधारण पेंशन 01.12.2025 से शुरू हो जाएगी।'

श्री दलजीत सिंह'हरियाणा के रेवाड़ी निवासी श्री दलजीत सिंह की शिकायत 150 दिनों से अधिक समय से लंबित थी। उनकी शिकायत एकराशिदान के भुगतान न होने और विकलांगता संबंधी लाभों की जांच से संबंधित थी। उन्होंने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत में भाग लिया। पीपीओ में 50% यानी 12,02,656/- रुपये का एकराशिदान दर्ज था लेकिन भुगतान लंबित था। रक्षा मंत्रालय के प्रयागराज स्थित पीसीडीए (पी) विभाग ने सूचित किया कि 12,02,656/- रुपये की एकराशिदान 10.11.2025 को उनके खाते में जमा कर दिया गया है।'

श्री नसीम अख्तर'जम्मू-कश्मीर के निवासी श्री नसीम अख्तर की शिकायत 150 दिनों से अधिक समय से लंबित थी। उनकी शिकायत अगस्त 2020 से लंबित पारिवारिक पेंशन मामले के निपटारे में देरी से संबंधित थी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में भाग लिया। मामला जनगणना संचालन विभाग का था। सीपीएओ के सीसी (पी) ने सूचित किया कि आदेश 24.12.2025 को जारी किया गया है और बिना किसी और देरी के बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।'सुश्री कंचन बाला'हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी सुश्री कंचन बाला की शिकायत 150 दिनों से अधिक समय से लंबित थी।

उनका मामला जनवरी 2021 से अविवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन मिलने में हो रही देरी से संबंधित था। उनके पिता स्वर्गीय श्री चूर सिंह बीएसएफ में कार्यरत थे। उन्होंने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बारे में बताया। बीएसएफ के अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि उनके मामले पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दस दिनों के भीतर इसकी समीक्षा कर इसका समाधान कर दिया जाएगा।'सुश्री मुक्ता चक्रवर्ती'असम के गुवाहाटी निवासी सुश्री मुक्ता चक्रवर्ती की शिकायत 150 दिनों से अधिक समय से लंबित थी। उनकी शिकायत स्वर्गीय श्री रजत भूषण चक्रवर्ती की अविवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन दिए जाने से संबंधित थी जो अक्टूबर 2020 से लंबित थी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में अपनी बात रखी थी।

इस साल 42 दिन विदेशी धरती पर रहें पीएम मोदी, 23 देशों की यात्रा की

(जीएनएस)।

वर्ष 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक कौशल और विदेश नीति के लिहाज से एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। 2015 के बाद यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री ने इतनी गहनता और सक्रियता के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।'आर्थिक चुनौतियों और बदलती भू-राजनीति के बीच, उनकी यात्राओं का उद्देश्य केवल द्विपक्षीय संबंध सुधारना नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना रहा है। घरेलू चुनावी व्यस्तताओं में कमी ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक समय और अवसर प्रदान किया।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के लिए सबसे व्यस्त साल रहा, जिसमें उन्होंने 11 यात्राओं के दौरान 23 देशों का दौरा किया। 2015 के बाद यह उनकी सर्वाधिक देशों की यात्रा है, जब उन्होंने 28 देशों का भ्रमण किया था। इस साल प्रधानमंत्री ने कुल 42 दिन विदेश में बिताए, जो उनके दूसरे कार्यकाल की तुलना में एक बड़ी बढ़त है। यह सक्रियता दशार्ती है कि भारत वैश्विक नेतृत्व की दिशा में कितनी तेजी से कदम बढ़ा रहा है।'ये भी पढें: ीं१ एल्लीं१ ढङ्क'३ू२: 2025 में भारतीय राजनीति ने क्या-क्या दिखा दिया? 5 बड़े फैक्टर से समझें सालाना लेखा-जोखा

इन देशों के दौरे पर गए पीएम मोदी' फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), मॉरीशस, थाईलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके), मालदीव, जापान, चीन, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, जॉर्डन, इथियोपिया

इस साल दो बार अमेरिका के दौरे पर गए पीएम मोदी'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में दो बार अमेरिका का दौरा कर द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती प्रदान की। फरवरी में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में वाशिंगटन डी.सी. की यात्रा कर रणनीतिक वार्ता की, जबकि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र और व्यापारिक चचाओं के लिए वे पुनः अमेरिका पहुंचे। इन दौरों का प्राथमिक उद्देश्य अमेरिकी आयात शुल्क से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना, रक्षा सहयोग बढ़ाना और दुर्लभ खनिजों की निर्बाध आपूर्ति हेतु साझेदारी को प्रगाढ़ करना रहा।'

गौतम गंभीर को कोचिंग से हटाने की तैयारी? बीसीसीआई की योजना को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

(जीएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीम इंडिया के लगातार खराब प्रदर्शन और कोच की रणनीतियों पर उठते सवालों के बीच एक बड़ी रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट के अनुसार टेस्ट कोच के रूप में उनकी छुट्टी करने की योजना पर काम हो सकता है लेकिन उनके पास भी पावर कम नहीं है।'दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई (BCCI) गंभीर को टेस्ट कोच के पद से हटाने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है, तो भारतीय क्रिकेट में यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव होगा। गंभीर की जगह टेस्ट कोच के लिए एक अन्य शख्स को अप्रोच करने की खबर भी आई है।

पीटीआई के अनुसार गंभीर को बोर्ड में मजबूत समर्थन प्राप्त है। टी20 में तो वह कोच बने रहेंगे लेकिन टेस्ट का कुछ पता नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन के बाद गंभीर के भविष्य पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट के ताकतवर गलियारों में मजबूत समर्थन हासिल है और जाहिर है कि अगर भारत टी20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखते हैं या कम से कम फाइनल तक पहुंचाते हैं, तो वह बिना किसी रुकावट के अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गंभीर का कार्यकाल टेस्ट क्रिकेट में कब तक रहता है।

गंभीर के पक्ष की बात यह है कि फिलहाल रेड बॉल फॉर्मेट में विकल्प बहुत कम हैं, खासकर तब, जब वीवीएस लक्ष्मण सीनियर टेस्ट टीम के कोच बनने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि एक बार लक्ष्मण को अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया।'भारत की टीम 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के साथ एक बार फिर मैदान पर उतरेगी।

इस दौरे में दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। इस सीरीज के समापन के बाद भारत 2026 टी20 विश्व कप की सह-मेजबानी की तैयारियों में जुट जाएगा।

सतना को सीएम मोहन यादव ने दी ऐतिहासिक सौगात, जानिए कैसे बनेगा 650 बेड का मेगा सरकारी अस्पताल

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सतना जिले को एक बड़ी और दूरगामी स्वास्थ्य सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को ₹383 करोड़ की लागत से बनने वाले 650 बिस्तरीय नवीन शासकीय चिकित्सालय भवन का विधिवत भूमिपूजन किया।'यह अत्याधुनिक अस्पताल सतना शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में बनेगा, जिससे पूरे विंध्य क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी।

भूमिपूजन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मजबूत, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। यह नया अस्पताल गरीब, मध्यम वर्ग और दूर-दराज के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा।'विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी राहत'यह बहुप्रतीक्षित परियोजना केवल सतना ही नहीं, बल्कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर सहित आसपास के 5 से 6 जिलों के लाखों नागरिकों के लिए राहत लेकर आएगी। वर्तमान में सतना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीमित बेड और संसाधनों के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंभीर रोगियों को भोपाल, जबलपुर या अन्य बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। नए अस्पताल के निर्माण से यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।'650 बेड वाला अस्पताल: स्वास्थ्य क्रांति की नींव'मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भूमिपूजन के दौरान

कहा कि यह अस्पताल विंध्य क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। परियोजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:'

बेड क्षमताः 650 बिस्तर, जो वर्तमान क्षमता से दोगुने से भी अधिक होगी

परियोजना लागतः ₹383 करोड़

स्थानः सतना शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर

आधुनिक सुविधाएं:

अत्याधुनिक डढऊ और क्ढऊ

हाईटेक कऊव और इमरजेंसी यूनिट

मल्टीपल ऑपरेशन थिएटर

आधुनिक डायग्नोस्टिक लैब

कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी सहित विशेष स्पेशलिटी वार्ड

निर्माण अवधिः लगभग 2 से 3 वर्ष (अनुमानित)

लाभार्थीः सतना सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के लाखों मरीज'मुख्यमंत्री ने कहा, "इस अस्पताल से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलेगी। गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज उनके जिले में ही उपलब्ध होगा।"'भव्य भूमिपूजन समारोह'भूमिपूजन समारोह में उत्साह और गरिमा का माहौल रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया।'इसके बाद मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों से कहा, "आप ही प्रदेश का भविष्य हैं। डॉक्टर बनकर आप समाज और प्रदेश की सेवा करेंगे। सरकार आपके लिए हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।"

छात्रों ने भी कॉलेज और अस्पताल से जुड़ी सुविधाओं को लेकर अपनी मांगें रखीं, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया।'क्यों जरूरी था नया अस्पताल' सतना शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। वर्तमान स्थिति यह है कि:

अस्पताल में लगभग 300 से 400 बेड ही उपलब्ध हैं

डढऊ में रोजाना हजारों मरीज पहुंचते हैं

कई स्पेशलिटी सेवाओं की कमी के कारण गंभीर मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ता है

क्षेत्र आदिवासी और ग्रामीण बहुल है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत ज्यादा है

यूपीः कोहरे की वजह से प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता हुई शून्य, इटावा रहा सूबे में सबसे ठंडा; पूवार्नुमान जारी

लखनऊ (जीएनएस)। यूपी में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। कोहरे के साथ गलन का असर कई जिलों में रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी की है।

प्रदेश में कोहरे के साथ ठंड का असर जारी है। सबसे ज्यादा असर तराई क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। शनिवार सुबह कई जिलों में काफी घना कोहरा होने की वजह से शून्य दृश्यता दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा।

आंचलिक मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि शनिवार सुबह शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज और कुशीनगर में काफी घना कोहरा रहा और दृश्यत शून्य दर्ज की गई। वहीं मेरठ, हरदोई, बहराइच और बलिया जिलों में 50 मीटर से कम दृश्यता दर्ज की गई। शनिवार को इटावा में न्यूनतम तापमान सबसे कम 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। बाराबंकी और चुर्क में 7 डिग्री, आगरा में 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ में न्यूनतत तापमान 10.8 डिग्री दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अभी दो दिन तक ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में घना से बहुत घना कोहरा होने के आसार हैं। तराई और दिल्ली एनसीआर में भी ऐसी ही स्थितियां रहेंगी।

उन्होंने कहा कि दो दिन बाद से जहां जहां बादल हैं वे छंटेंगे और कोहरे में कमी आएगी। इसके साथ ही तापमान में भी दो दिन बाद धीरे-धीरे बढ़ोतरी के आसार हैं। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 18

शारदा नदी में कार हादसाः बबलू मांझी ने बचाई चार जिंदगियां

(जीएनएस)।

पीलीभीत, उत्तराखंड के खटीमा से शारदा नदी पार कर रही एक कार शुक्रवार रात घने कोहरे के कारण नदी में गिर गई। यह हादसा पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र के धनारा घाट के पास हुआ। कार में चार युवक सवार थे, जिनकी जान बबलू मांझी ने बचाई।

हादसे का विवरण

कार सवार युवकों की पहचान लखीमपुर खीरी के संपूर्णनगर निवासी अर्जुन गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, आदित्य वर्मा और अनंत रघुवंशी के रूप में हुई। घने कोहरे में गाड़ी सड़क से उतरकर नदी में खिसक गई। युवकों ने शीशे तोड़कर बाहर निकलने के बाद आधा घंटे तक मदद की गुहार लगाई।

बबलू मांझी की बहादुरी

नदी किनारे रहने वाले पप्पू ने युवकों की चीखें सुन लीं और कल्पवास पर मौजूद बाबा राघवदास व अन्य साधुओं को बताया। बाबा ने बबलू मांझी को बुलाया, जिन्होंने साधुओं की मदद से लंबे बांस का सहारा देकर चारों को सुरक्षित किनारे खींच लिया। बबलू पहले भी 24 लोगों की जान बचा चुके हैं।

राहत और पुलिस कार्रवाई

नदी का ठंडा पानी युवकों को ठिठुरा रहा था। बाबा राघवदास ने आग जलाई और उन्हें गर्माहट दी। बाद में पुलिस पहुंची और सभी को घर भेज दिया। हजारा एसओ शरद यादव ने बताया कि रात में कार नहीं निकाल सकी, शनिवार सुबह स्थानीय लोग डूबी कार देखने आए। पुलिस अब कार को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है।

यह घटना कोहरे में सावधानी की याद दिलाती है। बबलू मांझी जैसे नायक समाज के लिए प्रेरणा हैं।

अवैध बालू खनन पर पुलिस की सख्तीः बरखेड़ा थाना पुलिस ने राजस्व टीम के सहयोग से ट्रैक्टर-ट्राली सीज

(जीएनएस)।

पीलीभीत।पुलिस अधीक्षक के सख्त निदेर्शों के अनुपालन में थाना बरखेड़ा पुलिस ने अवैध बालू खनन पर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्व विभाग की टीम के सक्रिय सहयोग से पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्राली को सीज कर लिया,

जो अवैध रूप से बालू का परिवहन कर रही थी। यह कार्रवाई नदी तटों पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है।पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई, जिसमें ट्रैक्टर-ट्राली चालक बालू से लदी मिली।

वाहन को सीज कर चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों में संतोष का भाव है, क्योंकि अवैध खनन से नदी तटों का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा था। पुलिस का यह प्रयास न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में भी सहायक सिद्ध होगा। आगे भी ऐसी सतत कार्रवाइयों का वादा किया गया है।

मिशन शक्ति-5 के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने महिलाओं-बालिकाओं को किया जागरूक

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मिशन शक्ति-5 अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों तथा साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

अभियान का उद्देश्यमिशन शक्ति-5.0 का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा 20 सितंबर 2025 को किया गया, जो शारदीय नवरात्रि से प्रारंभ होकर चरणबद्ध रूप से चल रहा है।

इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे अपराधों के खिलाफ सतर्क रहें।

थाना कोतवाली टीम ने क्षेत्र की महिलाओं से घर-घर जाकर बातचीत की और उन्हें सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित किया।

जागरूकता के प्रमुख बिंदुपुलिस टीम ने महिलाओं को दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, यौन अपराधों तथा साइबर ठगी जैसे मामलों की जानकारी दी।साइबर अपराधों में ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ और फेक न्यूज से बचाव के उपाय बताए गए।

हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 112 (इमरजेंसी), एंटी-रोमियो स्क्वायड तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का प्रचार किया।

यह प्रयास पीलीभीत जिले में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अपराधों पर अंकुश लगेगा और समाज सुरक्षित बनेगा।

जनशिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण में पीलीभीत प्रदेश में प्रथम स्थान

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आईजीआरएस, सीएम डैशबोर्ड, कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

(जीएनएस)।

पीलीभीत। जिलाधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गांधी सभागार में आयोजित बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, फीडबैक सुधार, राजस्व एवं कर-करेत्तर वसूली की समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।जिलाधिकारी ने बताया कि आईजीआरएस में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए जनपद को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने इसे बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में उद्यान, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, जल निगम, नगर पालिका, तहसील, परिवहन, बैंक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों और कर-करेत्तर वसूली पर विशेष बल देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली में प्रगति लाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता विद्युत, एआरटीओ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नमन फिजियोथैरेपी क्लिनिक में उन्नत मशीनों से जोड़ों के दर्द व नस-मांसपेशियों की बीमारियों का आधुनिक इलाज नमन फिजियोथैरेपी क्लिनिक एंड हेल्थ केयर सेंटर

(जीएनएस)।

पीलीभीत /बीसलपुर रामलीला रोड, जिला पीलीभीत ने आधुनिक सुविधाओं के साथ सेवाएं शुरू की हैं, जहां हड्डी, नस और मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कतों का इलाज किया जाएगा।क्लिनिक में पीडियाट्रिक, ऑथोर्पेडिक, स्पोर्ट्स इंजरी, न्यूरोलॉजिकल और सर्जिकल कंडीशन्स के लिए विशेष फिजियोथैरेपी की व्यवस्था है, जिससे हर आयु वर्ग के मरीजों को राहत मिल सकेगी।उन्नत मशीनें और थैरेपी

क्लिनिक में उन्नत पीढ़ी की कम्प्यूटरीकृत मशीनें, डिजिटल अल्ट्रासोनिक थैरेपी, कपिंग थैरेपी तथा ड्राई नीडलिंग थैरेपी जैसी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध कराई गई हैं, जो दर्द व सूजन को कम करने में मदद करती हैं।

डिजिटल अल्ट्रासोनिक थैरेपी से नरम ऊतकों में रक्त संचार बढ़ता है, सूजन घटती है और चोटिल हिस्से की हीलिंग तेज होती है, जबकि ड्राई नीडलिंग से जकड़ी हुई मांसपेशियों के ट्रिगर पॉइंट ढीले होकर दर्द में तेजी से आराम दिलाते हैं।जोड़ों के दर्द और चलने-फिरने में लाभ

फिजियोथैरेपी से घुटने, कमर, गर्दन, कंधे तथा रीढ़ के दर्द में दवाओं पर निर्भरता कम होती है और मांसपेशियां मजबूत होकर जोड़ सुरक्षित रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित फिजियोथैरेपी से जोड़ों की जकड़न कम होती है, मूवमेंट बेहतर होता है और मरीज रोजमर्रा के काम पहले की तरह आसानी से कर पाते हैं।स्पोर्ट्स इंजरी और पोस्ट-सर्जरी के लिए मददगार

क्लिनिक में खेल संबंधी चोटें, लिगामेंट की समस्या, फ्रैक्चर के बाद की जकड़न तथा ऑपरेशन के बाद की कमजोरी के लिए विशेष रीहैब प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे। फिजियोथैरेपी से ऐसे मरीजों की मसल स्ट्रेंथ बढ़ाकर दोबारा चोट लगने की आशंका कम की जा सकती है और वे जल्दी से अपने काम या खेल में वापसी कर पाते हैं।लोगों से अपील

डॉ. आकाश (पीटी) एमपीटी ऑर्थो की देखरेख में चल रहे नमन फिजियोथैरेपी क्लिनिक ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि जो भी जोड़ों के दर्द, नसों की समस्या, लकवा, खेल चोट या ऑपरेशन के बाद कमजोरी से जूझ रहे हों, वे समय पर फिजियोथैरेपी लेकर अपनी जीवन-शैली सुधारें। विशेषज्ञ बताते हैं कि सही समय पर शुरू की गई फिजियोथैरेपी कई मामलों में ऑपरेशन की जरूरत टाल सकती है और मरीजों को सुरक्षित, बिना साइड इफेक्ट के इलाज का विकल्प देती है।पताः नमन फिजियोथैरेपी क्लिनिक एंड हेल्थ केयर सेंटर, बीसलपुर रामलीला रोड, जिला पीलीभीत।

बीसलपुर मंडी में भ्रष्टाचार चरम पर, सेंटर इंचार्ज की मनमानी से किसान त्रस्त

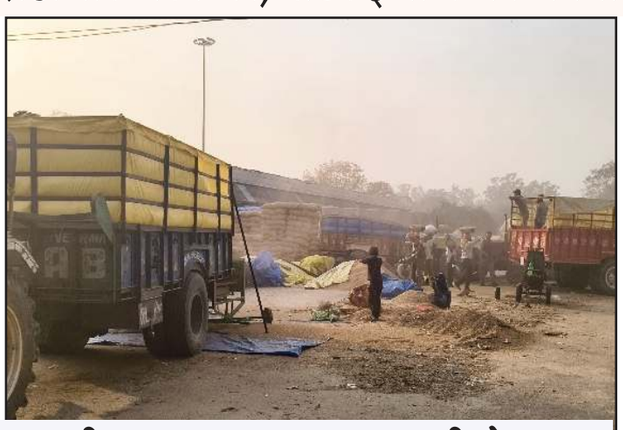

बीसलपुर (पीलीभीत)। बीसलपुर नवीन मंडी में धान खरीद में भ्रष्टाचार का खेल चरम पर है। मंडी सचिव, एमओ और सेंटर इंचार्ज की मिलीभगत से बिचौलिये खुलेआम किसानों की लूट कर रहे हैं। तौल में हेराफेरी, बोली प्रक्रिया में लापरवाही और धान निस्तारण में देरी से किसान बेहाल हैं। एक माह से मंडी में पड़ा किसानों का धान सड़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई अब तक नहीं हुई।किसानों का आरोप है कि सेंटर इंचार्ज मनमानी कर रहे हैं। वे अपने पसंदीदा बिचौलियों को लाभ पहुँचा रहे हैं जबकि छोटे किसानों के धान को "नमी अधिक" बताकर खारिज किया जा रहा है। धान की तौल घटिया मशीनों से कराई जाती है, जिनमें जानबूझकर वजन घटाया जाता है। एक किसान ने बताया, सेंटर इंचार्ज ने कहा नमी ज्यादा है, पर सच्चाई यह है कि बिचौलियों का कमीशन काटा जा रहा है।ह्वकृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1966 और उत्तर प्रदेश मंडी नियमावली के अनुसार तौल पारदर्शी होनी चाहिए, उल्लंघन करने पर तीन वर्ष की सजा और जुमार्ने का प्रावधान है। इसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों में छेड़छाड़ खुले आम की जा रही है। स्टोरेज की भी भारी कमी है, जिससे किसानों का धान खुले में सड़ रहा है और चूहों से भी नुकसान हो रहा है।पिछले एक महीने में 50 से अधिक किसानों ने मंडी सचिव और सेंटर इंचार्ज के खिलाफ शिकायत की, मगर मंडी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसान संगठनों ने चेताया है कि यदि जल्द जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। किसानों की मांग है कि मंडी सचिव और सेंटर इंचार्ज को निलंबित कर बिचौलियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए।कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल तौल प्रणाली और सीसीटीवी निगरानी से ही पारदर्शिता लाई जा सकती है। फिलहाल मंडी व्यवस्था पूरी तरह फेल दिख रही है और सरकारी 'किसान सम्मानह्व योजनाएं सवालों के घेरे में हैं।

पीलीभीत में रक्फ़प्रक्रिया पूरीः 2.86 लाख मतदाता सूची से बाहर

(जीएनएस)।

पीलीभीत जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (रक्फ़) प्रक्रिया 26 दिसंबर रात 12 बजे लॉक हो गई। इस दौरान पुरानी मतदाता सूची से 2 लाख 86 हजार से अधिक मतदाताओं को हटाया जाएगा। साथ ही, 68 हजार से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी होंगे।

मुख्य आंकड़े

- कुल मतदाताः 14.67 लाख
- मैप किए गए मतदाताः 11.99 लाख
- सूची से बाहर होने वालेः 2.86 लाख+
- नोटिस प्राप्त करने वालेः 68 हजार+
- बीएलओ की संख्याः 1522

रक्फ़ की समयसीमा 4 दिसंबर से बढ़ाकर 26 दिसंबर की गई थी। अंतिम दिन बीएलओ ने फोन कॉल से जानकारी इकट्ठा की और फॉर्मों को मैप किया। कई मतदाताओं ने कंट्रोल रूम में फॉर्म जमा किए, जबकि कुछ ने बार-बार कहने पर भी फॉर्म नहीं दिए—उनका डेटा अलग से जुटाया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पोर्टल रात 12 बजे अपडेट हो चुका है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए की गई, जिससे चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बने।

कलसेन बाबा मंदिर में दानपत्र विवादः सेवादार नागा बाबा गिरी ने एस .डी एम. को सौंपा शिकायती पत्र

(जीएनएस)।

पीलीभीत जिले के बीसलपुर क्षेत्र में कलसेन बाबा स्थान पर 42 वर्षों से सेवादार नागा बाबा गिरी ने वाल्मीकि रिंकू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। आरोप है कि टिंकू उर्फ बंटू ने बाबा की मणि पर कली मंदिर बनवाकर दानपत्र स्थापित किया और दान की राशि मांस-मदिरा पर उड़ा रहा है। बाबा द्वारा रोकने पर धमकियां दी जा रही हैं।पीड़ित का विवरणनागा बाबा गिरी पुत्र बालकिशन मिस्त्री, स्थान कलसेन बाबा, बीसलपुर, पीलीभीत के निवासी हैं। वे 42 वर्षों से कलसेन बाबा स्थान पर समर्पित सेवादार के रूप में सेवा कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार, स्थानीय वाल्मीकि टिंकू उर्फ बंटू पुत्र जगदीश, मोहल्ला दुबे, बीसलपुर ने बाबा की पवित्र मणि पर अनधिकृत कली मंदिर का निर्माण कराया।मुख्य आरोपी टिंकू ऊर्फ ने मंदिर में दानपत्र रखा और भक्तों के दान की राशि का दुरुपयोग मांस-मदिरा पर किया।जब बाबा ने दान की अनियमितता पर रोक लगाने की कोशिश की, तो टिंकू ने बार-बार धमकियां दीं।यह विवाद धार्मिक स्थल की पवित्रता को भंग करने वाला है, जहां दान भक्तों की आस्था का प्रतीक होता है।प्रशासनिक कार्रवाई की मांगपीड़ित ने उपजिलाधिकारी बीसलपुर से तत्काल जांच और टिंकू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय स्तर पर मंदिर प्रबंधन और दानपत्र की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की गई। प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है,